यूपी में पांच गीगावाट डाटा सेंटर क्लस्टर बनेंगे

लखऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश सरकार ने बजट 2026–27 में प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। बजट में 5 गीगावाट क्षमता के 4–5 डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

प्रथम चरण में वर्ष 2030 तक 5 गीगावाट क्षमता विकसित करने तथा वर्ष 2047 तक इसे 40 गीगावाट तक विस्तारित करने का विजन रखा गया है।

वर्तमान परिदृश्य में भारत विश्व के बड़े डाटा उत्पादक देशों में शामिल है, किंतु डाटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की यह पहल राष्ट्रीय डिजिटल स्वायत्तता और निवेश आकर्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बजट में स्पष्ट किया गया है कि डाटा सेंटर क्लस्टर विकास के लिए भूमि, गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त जल संसाधन, उच्च क्षमता वाली बैण्डविथ तथा कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही त्वरित स्वीकृति प्रणाली और निवेशक-अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है। प्रदेश सरकार का आकलन है कि डाटा सेंटर स्थापना पूंजी-गहन क्षेत्र है, जिसमें प्रति मेगावाट 70–80 करोड़ रुपये तक का निवेश संभावित है।

स्टार्ट अप को बढ़ावा

बजट में यह भी संकेत दिया गया है कि जहां-जहां डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित होंगे, वहां समेकित डिजिटल टाउनशिप और नवाचार आधारित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाएगा। इससे स्टार्टअप, आईटी सेवाओं, क्लाउड कम्प्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और एआई आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री के संबोधन में व्यक्त डिजिटल भविष्य के विजन के अनुरूप यह बजट प्रावधान उत्तर प्रदेश को पारंपरिक औद्योगिक विकास से आगे बढ़ाकर प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में ले जाने का संकेत देता है।